

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक **01.07.25**

संख्या-7 / मुक0-08-13 / 2018सा0प्र0वि0.....\1\237.../भारत संविधान (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना से परामर्श के पश्चात् माननीय पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधाएं नियमावली, 2025 ।**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना:—(1) यह नियमावली “सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधाएं नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह नियमावली अधिसूचना की निर्गत तिथि से प्रवृत्त होगी और यह बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019 एवं तत्संबंधी अन्य प्रावधानों को अवक्रमित करेगी।  
(4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जिसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद धारित किया हो या उनके जीवित पति/पत्नी पर लागू होगी।
2. परिभाषाएँ:—इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (i) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय, पटना;
  - (ii) “पूर्व मुख्य न्यायाधीश” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो;
  - (iii) “भूतपूर्व न्यायाधीश” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो;

- (iv) "पति/पत्नी" से अभिप्रेत है पद पर रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश का यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी;
- (v) "घरेलू सहायता" से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के खर्च पर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश, या उनकी जीवित पत्नी/उनके जीवित पति को उपलब्ध कराये जाने वाले सहायक की सहायता।

### 3. पात्रता:-

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या यथास्थिति उनके पति/पत्नी उच्च न्यायालय के खर्च पर घरेलू सहायक(कों), चालक(कों), सचिवीय सहायता, सुरक्षा और टेलीफोन सुविधा की सेवायें प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

- (i) किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को ऐसी अथवा समान सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही हो; को घरेलू सहायक(कों), चालक(कों), सचिवीय सहायता, सुरक्षा और टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी,
- (ii) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, किसी कार्यालय, पद अथवा कार्यभार पर उनकी नियुक्ति/कार्यभार की अवधि के दौरान घरेलू सहायक(कों), चालक(कों), सचिवीय सेवा की सुविधा तथा अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे सिवाय इसके कि ऐसी नियुक्ति/कार्यभार में क्रमशः घरेलू सहायक, चालक और सचिवीय सेवा की सुविधा तथा अन्य लाभ उपलब्ध न हों।

### 4. घरेलू सहायक(कों) का चयन:-

पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश या यथास्थिति, उनके पति/पत्नी अपने विवेक से घरेलू सहायक(कों)/चालक(कों) के रूप में लगाये जाने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकेंगे।

### 5. प्रतिपूर्ति:-

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या यथास्थिति, उनके पति/पत्नी को घरेलू सहायक/चालक रखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश या पति/पत्नी को

₹ 55,000/— प्रति माह तथा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या पति/पत्नी को ₹ 60,000/— प्रति माह एकमुश्त राशि प्रदान किया जायेगा।

**6. स्थायी कर्मचारी की अन्यत्र अस्थायी नियुक्ति:—**

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या यथास्थिति, उनके पति/पत्नी उच्च न्यायालय की अंतिम ग्रेड सेवा में कार्यरत अधिकतम दो कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अनुरोध कर सकते हैं, जिसमें से एक चालक हो सकता है; (या)

यदि उच्च न्यायालय की अंतिम ग्रेड सेवा में कार्यरत कोई कर्मचारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या यथास्थिति, उनके पति/पत्नी की सेवा करने के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है और ऐसे कर्मचारी(यों) की सेवाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या यथास्थिति, उनके पति/पत्नी को स्वीकार्य हो;

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी के साथ काम करने के लिए अस्थायी नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकेगी जब तक कि घरेलू सहायता के लिए रखा गया ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु न प्राप्त कर ले और/या जबतक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी इस सुविधा के हकदार हों।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या यथास्थिति उनके पति/पत्नी, नियम-5 में निर्धारित पूर्ण प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे यदि उच्च न्यायालय द्वारा दो कर्मचारी उपलब्ध कराये जाते हैं; या यदि उच्च न्यायालय द्वारा केवल एक कर्मचारी उपलब्ध कराया जाता है तो नियम-5 में उल्लिखित प्रतिपूर्ति के 50 प्रतिशत के हकदार नहीं होंगे।

स्थायी कर्मचारी की अन्यत्र अस्थायी नियुक्ति उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के विवेक से होगी तथा कर्मियों की उपलब्धता के अधीन होगी।

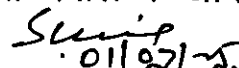
**7. सेल फोन/लैंडलाइन व्यय, इंटरनेट शुल्क, सचिवीय सेवा एवं सुरक्षा सेवाएं:—**

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या यथास्थिति उनके पति/पत्नी को सचिवीय सेवा, सुरक्षा सेवा के किराये, इंटरनेट सेवा, लैंडलाइन और/या मोबाइल कॉल के खर्च के लिए ₹ 15,000/— प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। हालांकि

यह उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगी, जब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या यथास्थिति उनके पति/पत्नी ने कोई कार्यभार स्वीकार किया हो और उन्हें उस कार्यभार के दौरान उस कार्यभार के तहत वही सुविधा प्रदान की गयी हो।

8. नियम-5 एवं 7 में उल्लिखित राशियों में प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात 5% की वृद्धि की जायेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,


  
(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/मुक0-08-13/2018 सा0प्र0वि0 ...11.9.37.../पटना-15, दिनांक 01.7.25

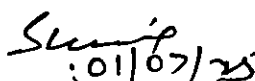
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना और ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को इसकी सी0डी0 सहित दो प्रतियों में असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाएँ।

  
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-7/मुक0-08-13/2018 सा0प्र0वि0 ...11.9.37.../पटना-15, दिनांक 01.7.25

प्रतिलिपि-महाधिवक्ता, बिहार (निजी सचिव), उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-प्रभारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोषांग, उच्च न्यायालय, पटना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-15 दिनांक 01.07.2025 के प्रसंग में/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/मुक0-08-13/2018 सा0प्र0वि0 ...11.9.37.../पटना-15, दिनांक 01.7.25

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवा/संवर्ग अधिनियम/नियमावली/विनियमावली आइकन के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

**Government of Bihar**  
**General Administration Department**

**Notification**

Patna-15, Date 01.07.2025

No-7/Muk.-08-13/2018 GAD 11.9.7... /In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India (as amended from time to time) the Governor of Bihar, after consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to regulate the Retired Chief Justices and Judges Domestic Help(s) and Other Benefits:-

**Retired Chief Justices and Judges Domestic Help(s) and Other Benefits Rules, 2025.**

1. **Short title, extent, commencement and application:-** (1) These Rules may be called the "Retired Chief Justices and Judges Domestic Help(s) and Other Benefits Rules, 2025"
  - (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
  - (3) These Rules shall come into force from the date of notification and this will be in supersession of the Rules known as "Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the High Court Rules, 2019 and other provisions".
  - (4) The Rules shall apply to a person who has held office either as a Chief Justice or as a Judge of the Patna High Court or their surviving spouse.
2. **Definitions:- In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context-**
  - (i) "High Court" means the High Court of Judicature at Patna.
  - (ii) "Former Chief Justice" means a person who has held office of the Chief Justice of the High Court.
  - (iii) "Former Judge" means a person who has held office of a Judge of the High Court.
  - (iv) "Spouse" means the surviving wife or husband as the case may be, of a Former Chief Justice or Former Judge upon his or her death while in office or after retirement.
  - (v) "Domestic Help" means the assistance of a helper to be provided to a Former Chief Justice or a Former Judge of High Court, or to his or her spouse at the expense of the High Court.

### **3. Eligibility:-**

A retired Chief Justice or a Judge of the High Court or their spouse, as the case may be, shall be entitled to avail the services of Domestic Help(s), Driver(s), Secretarial Assistance, Security and Telephone facility at the expenses of the High Court, subject to the following conditions.

- (i) The facility of Domestic Help(s), Driver(s), Secretarial Assistance, Security and Telephone facility shall be provided to the retired Chief Justice/Judge or their spouse, if he/she is not availing such or similar facility from any other High Court,
- (ii) The retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, on his/her appointment to any Office, post or assignment shall not be entitled to the facility of Domestic Help(s), Driver(s), Secretarial Service and other benefits during the tenure of such appointment/assignment except where such appointment/assignment does not provide the facility of any domestic Help(s), Driver(s) and Secretarial Service and other benefits, respectively.

### **4. Selection of Domestic Help(s):-**

The retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, may at her or his discretion select persons to be engaged as Domestic Help(s)/Driver(s).

### **5. Reimbursement:-**

To enable the retired Chief Justice/Judge, or their spouse, as the case may be to engage domestic help(s)/Driver(s) High Court shall provide a consolidated amount of Rs. 55,000/- per month to a retired Judge or spouse and Rs. 60,000/- per month to a retired Chief Justice or spouse.

### **6. Secondment of a Permanent Employee:-**

The retired Chief Justice/Judge or their spouse may request to avail the services of maximum of two employees working in Last Grade Service of the High Court, one of whom may be a Driver; (OR)

If any employee working in Last Grade Service of the High Court furnishes to the Registrar General of the High Court, a request in writing to serve a retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, and the services of such employee(s) is/are acceptable to the retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be;

They may be seconded to work with the retired Chief Justice/Judge or their spouse until the employee(s) attain(s) the age of superannuation and/or so long as the retired Chief Justice/Judge or their spouse is entitled to this facility.

It is made clear that if employees of the High Court are seconded, the retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, are not entitled to full reimbursement as stipulated in Rule- 5 if two employees are provided by the High Court; or 50% of the reimbursement mentioned in Rule-5, if only one employee of the High Court is provided.

The said secondment shall be at the discretion of the Hon'ble Chief Justice and subject to availability of staff.

**7. Cell Phone/Landline Expenses, Internet Charges, Secretarial Services and Security Services:-**

The retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, shall also be paid Rs. 15,000/- per month towards expenses of rentals and calls of Mobiles and/or Landline, internet service, secretarial services and security service. However, this facility shall not be available if the retired Chief Justice/Judge or their spouse, as the case may be, has accepted some assignment and has been provided the same facilities under that assignment, during the continuation of such assignment.

**8. The amounts mentioned in Rules-5 & 7 shall be increased by 5% after every one year.**

By order of the Governor of Bihar

  
(Sunil Kumar Tiwari)

Under Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Muk.-08-13/2018GAD .....11937...../Patna-15, dated 01.07.2025

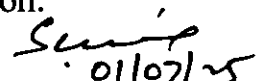
Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

  
Under Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Muk.-08-13/2018GAD .....11937...../Patna-15, dated 01.07.2025

Copy forwarded to the Advocate General, Bihar (P.S), High Court, Patna/Accountant General (A&E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/Additional Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.- 15 dated 01.07.2025/Secretary, Bihar Legislative Council, Patna/Secretary, Legislative Assembly, Patna/Secretary, Law Department, Bihar, Patna/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/All Principal District & Sessions Judges/All Departments for information and necessary action.

  
Under Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Muk.-08-13/2018GAD .11937..... /Patna-15, dated .01.07.2025

I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action for uploading under the icon of main head of Acts/Rules/Resolutions related to various Service/Cadre on Departmental website.

*Sumit*  
01/07/25  
Under Secretary to the Govt.